

19 वस्तुओं के आयात शुल्क में वृद्धि

संदर्भ

हाल ही में सरकार ने जेट ईंधन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर सहित कुल 19 वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने का नरिणय लिया है। यह नरिणय 29 सितंबर, 2018 की मध्यरात्रि से प्रभावी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पछिले वित्त वर्ष में इन 19 उत्पादों का कुल आयात बलि 86,000 करोड़ रुपए रहा था। उल्लेखनीय है कि सरकार ने चालू खाता घाटा (CAD) पर अंकुश तथा रुपए की गिरावट में कमी लाने के लिये यह कदम उठाया है।

चालू खाता घाटा (CAD)

- चालू खाते के अंतरगत मुख्यतः तीन प्रकार के लेन-देन, जसिमें पहला वस्तुओं व सेवाओं का आयात-नरियात और दूसरा कर्मचारियों व वदिशी नविश से प्राप्त आय एवं खर्च तथा तीसरा करंट ट्रांसफर (वदिशों से प्राप्त अनुदान राशि, उपहार और वदिश में बसे कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली रेमिटेंस की राशि) को शामिल किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि वदिशी मुद्रा के अंतः और ब्राह्य प्रवाह के बीच के अंतर को चालू खाता घाटा (CAD) कहते हैं।
- यदा यह अंतर नकारात्मक होता है तो इसे चालू खाता घाटा (CAD) कहते हैं और सकारात्मक होने पर इसे चालू खाते का सरप्लस कहा जाता है।
- चालू खाता घाटा में उतार-चढ़ाव का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। यही मुख्य कारण है कि इसे GDP प्रतशित के रूप में व्यक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि CAD में सबसे बड़ा हिससा व्यापार घाटे का होता है।

उद्देश्य

- मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर शुल्क उपाय किये हैं।
- जसिका मुख्य उद्देश्य कुछ आयात वस्तुओं का आयात घटाना है ताकि इन बदलावों से चालू खाता घाटा (CAD) को सीमित किया जा सके तथा बढ़ते CAD से नरियात को बढ़ावा देने के लिये व्यापक उपायों को स्थापित किया जा सकेगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, “बढ़ते कैंड के मुद्दे से निपटने के लिये सरकार गैर आवश्यक वस्तुओं का आयात घटाएगी और नरियात बढ़ाएगी।”

कनि वस्तुओं पर बढ़ाया गया आयात शुल्क

- वित्त मंत्रालय के मुताबिक, पछिले वित्त वर्ष में 19 उत्पादों का कुल आयात बलि 86,000 करोड़ रुपए रहा था।
- कुल मलिकर 19 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। उल्लेखनीय है कि इनमें स्पीकर, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, रेडयिल कार टायर, आभूषण उत्पाद, कुछ प्लास्टिक का सामान तथा सूटकेस आदि शामिल हैं।
- इसी तरह कमप्रेसर, स्पीकर और फुटवियर पर आयात शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 10, 15 और 25 प्रतशित किया गया है।
- रेडयिल कार टायर पर आयात शुल्क बढ़ाकर 10 से 15 प्रतशित किया गया है। तराशे और पालशि किये गए, अरद्ध प्रसंस्कृत और प्रयोगशाला में बनाए गए एवं रंगीन रत्नों पर आयात शुल्क को 5 प्रतशित से बढ़ाकर 5 प्रतशित किया गया है।
- इसी प्रकार आभूषण, सुनार, चाँदी के बरतन बनाने वालों की वस्तुओं पर आयात शुल्क को 15 से बढ़ाकर 20 प्रतशित कर दिया गया है।
- स्नानघर का सामान, पैकगि सामग्री, रसोई के सामान, ऑफिसि स्टेशनरी, सजावट वाली शीट, मनकों, चूड़ियाँ, ट्रंक, सूटकेस और यात्रा बैग पर अब 10 की बजाय 15 प्रतशित सीमा शुल्क लगेगा।

वर्तमान नरिणय का प्रभाव

- वस्तुओं के एक समूह पर 20% तक आयात शुल्क को बढ़ाने का नरिणय इन उत्पादों की खपत को कम कर सकता है, खासतौर पर उस समय जब डॉलर के मुकाबले रुपए की स्लाइड पहले से ही इन वस्तुओं को महँगी बनाती है।
- यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार का कदम एक मनोवैज्ञानिक 'टपिगि प्वाइंट' में बदल जाता है जसिसे आयात वस्तुओं पर शुल्क वृद्धि से खपत व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है।
- यदा ऐसा होता है, तो इन वस्तुओं में से कुछ के घरेलू उत्पादन में अधिक नविश को बढ़ावा मलि सकता है।
- उल्लेखनीय है कि विमानन टरबाइन ईंधन पर टैरफि को शून्य से बढ़ाकर 5% तक किया गया है जसिसे घरेलू एयरलाइन ऑपरेटर्स की समस्याएँ बढ़ सकती हैं, साथ ही पहले से ही रुपए और बढ़ती तेल की कीमतें CAD मार्जनि को चोट पहुँचा रही हैं।
- वही वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और ईरान पर लगा प्रतबिंध भारत को अन्य तेल आपूर्तकिर्त्ताओं की तलाश हेतु मज़बूर कर सकता है।

आगे की राह

- नीति निर्माताओं को नरियात व्यापार को बढ़ावा देने के लिये नवीन पर्यासों को अपनाने की आवश्यकता है ।
- उल्लेखनीय है कि जीएसटी के चलते छोटे नरियातकों की कामकाजी पूंजीगत कमी ने नरियात को बुरी तरह प्रभावित किया गया है ।
- ऐसे में चीन से बाहर आने वाले वयितनाम और बांग्लादेश जैसे देशों की कुछ शर्म-केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं को लुभाने हेतु काम करने की आवश्यकता है ।
- यह एक वडिंबना है कि कोयले के भंडार की प्रचुरता के बावजूद, थर्मल कोयला भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते आयातों में से एक है । यह संपूर्ण कोयला उत्पादन और उपयोग श्रृंखला के आधुनिकीकरण करने में कम नविश का परिणाम है जसै शीघ्रता से संज्ञान में लिया जाना चाहिये ।
- तेल की बढ़ती कीमतों से तेल का आयात महंगा होगा जसिके चलते भारत में महंगाई दर बढ़ने की संभावना है । बढ़ी हुई महंगाई दर का असर बुनियादी तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं पर भी पड़ेगा ।
- अतः सरकार को CAD को सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक या उससे भी अधिक बढ़ाने के लिये संरचनात्मक असंतुलन को कम करने में तत्परता लाने की आवश्यकता होगी ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/think-big-on-import-duty-hike>

